17 OCT 3 2026.qxd 16-10-2026 23:20 Page 1



भाजन

तलाकके बाद...

दीप्ती और ...



प्रयागराज, शनिवार १७ अक्तूबर, २०२६ सौर ३१, आश्विन शुक्ल ७, २०८३ वि.। वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज (रीवा संस्करण), कानपुर (झांसी संस्करण), लखनऊ, आगरा, बरेली, हल्द्वानी,पटना (कोलकाता संस्करण), रांची (धनबाद संस्करण) तथा जमशेदपुर से प्रकाशित | नगर संस्करण पृष्ठ १२, मूल्य ३.०० रुपये

हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, साजिश का विरोध करते हैं-अखिलेश

लखनऊ (आससे)। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव आयोग पहले विशेष गहन पुनरीक्षण के जरिये लोगों के नाम काट रहा है और फिर जोड़ने के नाम पर धांधली करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि एक वोटर के नाम कई जगह जोड़े जा रहे हैं जिससे कि भाजपा के पक्ष में फर्जी मतदान करवाया जा सके। अखिलेश यादव ने प्रेस कांफ्रेंस में एक युवा को बुलाया और कहा कि इनका वोट कई जगह है जिसका खुलासा इन्होंने खुद किया है। ये युवा एक जगह ही वोट करेगा पर जहां-जहां इनका नाम है वहां कोई और भाजपा के पक्ष में मतदान करेगा। उन्होंने कहा कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं हैं बल्कि इसके जरिये चुनाव लूटने की जो साजिश हो रही है उसके खिलाफ हैं। इस मौके पर अलग-अलग दलों के नेता सपा में शामिल हो गये। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोगों की चोरी पकड़ ली गयी है इसलिए ये लोग घबराए हुए हैं। ये लोग जानते हैं कि उनका कोर वोटर भी इनसे दूर जा रहा है इसलिए ये धांधली कर रहे हैं क्योंकि कोई भी सच्चा सनातनी मंदिर में दान चोरी नहीं कर सकता है। अब जनता इन्हें ठीक से पहचान चुकी है। शामे अली (बसपा-पीलीभीत), रवि प्रताप (बदायूं), विद्युत अग्रहरि, राजपाल सैनी, पूर्व राज्यसभा संसाद, पूर्व मंत्री, नन्द किशोर पुंडीर (बसपा से गाजियाबाद के प्रत्याशी), कमल गौतम (अजाद समाज पार्टी), हरिवीर मालिक, भाजपा शामली, शोकेन्द्र, संजीव प्रधान रालोद, सीवान सैनी, खतौली, राजेन्द्र मलिक रालोद, विजेंद्र मलिक, शुभम मलिक सपा में शामिल हुए।

प्रदेश के ७० हजार शिक्षकों की पदोन्नति का रास्ता साफ

सात नवम्बर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश

लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की करीब दस साल बाद पदोन्नति प्रक्रिया शुरू हुई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने सात नवंबर तक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इससे लगभग 70 हजार शिक्षकों को लाभ मिलने की संभावना है। पदोन्नति के लिए अनुभव, वरिष्ठता सूची और शिक्षक पात्रता परीक्षा की शर्तें निर्धारित की गई हैं। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों के शिक्षकों की लगभग दस साल पदोन्नति करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करते हुए शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची जारी करते हुए रिक्तियों के सापेक्ष सात नवंबर तक पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए हैं। इसका लाभ प्रदेश के लगभग 70 हजार शिक्षकों को मिलने की संभावना है। बेसिक में लंबे समय से पदोन्नति की प्रक्रिया लंबित है। काफी समय से टीईटी को लेकर भी मामला न्यायालय में चला है। इसी क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद ने सभी बीएसए को शिक्षकों की अंतिम वरिष्ठता सूची तैयार करने के लिए विस्तृत निर्देश व प्रक्रिया जारी करते हुए इसे 23 अक्तूबर तक परिषद को मेल पर उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। परिषद सचिव सुरेंद्र तिवारी ने कहा है कि न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में नए जिला आवंटन के फलस्वरूप कार्यभार ग्रहण करने वाले अभ्यर्थियों की वरिष्ठता का निर्धारण उनकी पहली नियुक्ति तिथि से करने के निर्देश हैं। जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक के लिए जूनियर स्कूल की स्थायी सहायक अध्यापक के लिए न्यूनतम पांच साल का अनुभव होना चाहिए। इसी तरह सीनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक के लिए जूनियर बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापक व सीनियर बेसिक स्कूल के सहायक अध्यापक पद पर न्यूनतम तीन साल का अनुभव चाहिए। वरिष्ठता सूची व पदोन्नति के लिए जिला स्तर पर डायट प्राचार्य की अध्यक्षता वाली समिति होगी। इसमें बीएसए, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज के वरिष्ठ प्रधानाचार्य, डीएम द्वारा नामित भाषा विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति वरिष्ठता सूची तैयार करते हुए आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगी। सचिव ने कहा है कि पात्रता सूची में शिक्षकों के सामने टीईटी उत्तीर्ण होने का पूरा विवरण दिया जाएगा। उन्होंने केवल प्राथमिक स्तर की टीईटी की है, केवल उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी की है, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी पास हैं या नहीं हैं, का उल्लेख किया जाएगा। जो शिक्षक प्राथमिक स्तर की टीईटी पास हैं वे प्राथमिक विद्यालयों में और जिनके द्वारा केवल उच्च प्राथमिक स्तर की टीईटी की गई है, वे केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में, जिन्होंने दोनों की है, वे दोनों में तैनाती के लिए अर्ह होंगे।

मुंबई में 15.87 करोड़ की ड्रग्स जब्त

मुंबई (आससे)। मुंबई पुलिस ने दो दिन के विशेष अभियान में 15.87 करोड़ रुपये के नशीले पदार्थ जब्त किए और 21 फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया। इस दौरान 72 मामले दर्ज हुए और 40 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट तामील किए गए। पुलिस ने पांच आरोपियों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई की। मुंबई पुलिस ने नशे के सौदागरों की नींद उड़ा दी है! शहर में ड्रग्स का कारोबार करने वालों के खिलाफ पुलिस ने ऐसा जबरदस्त डंडा चलाया है कि अपराधियों में हड़कंप मच गया है। हाल ही में 14 और 15 अक्तूबर को मुंबई पुलिस ने दो दिन का एक विशेष अभियान चलाया। इस ताबड़तोड़ कार्रवाई में पुलिस ने कुल 15 करोड़ 87 लाख रुपये की खतरनाक ड्रग्स जब्त की है। पुलिस ने शहर के अलग-अलग कोनों से करीब 46 किलो ड्रग्स बरामद की। इसमें गांजा, एमडी ड्रग, ब्राउन शुगर, चरस, कोकीन और एलएसडी जैसी चीजें शामिल हैं। इसके अलावा कफ सिरप की 9,540 बोतलें और 9 लाख रुपये से ज्यादा का कैश भी हाथ लगा है।पुलिस सिर्फ नया माल ही नहीं पकड़ रही थी, बल्कि पुराने मामलों में फरार चल रहे 21 बदमाशों को भी दबोच लिया। वहीं, कोर्ट के आदेश पर 40 लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट भी निकाले गए। सबसे बड़ी बात यह रही कि पुलिस ने एक शातिर ड्रग्स गैंग का पर्दाफाश किया, जिसके पांच सदस्यों पर मकोका जैसा सबसे सख्त कानून लगाया गया है, ताकि ये आसानी से जेल से बाहर न आ सकें। नशे के इस काले कारोबार पर चोट करने के लिए पुलिस ने बुलडोजर का भी इस्तेमाल किया। ड्रग्स बेचने वालों के 20 अवैध मकानों और ढांचों को ढहा दिया गया। साथ ही, नशे के अड्डे बनीं 145 पान की दुकानों को भी हटा दिया गया।

२१ फरार आरोपित भी गिरफ्तार

कनिष्ठ विश्लेषक भर्ती मामले में यूपीएफएसडीए की बड़ी कानूनी जीत

लखनऊ (आससे)। उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग (यूपीएफएसडीए) को कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 पदों पर भर्ती के मामले में बड़ी कानूनी जीत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ की दो सदस्यीय खंडपीठ ने भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के पद के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शैक्षिक योग्यता वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप है। अदालत ने संबंधित भर्ती नियमों को वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी।शैक्षिक योग्यता और भर्ती नियमों को दी गई थी चुनौती मामला विज्ञापन संख्या 04/2024 के तहत कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) के 417 पदों पर सीधी भर्ती से जुड़ा है। पंकज कुमार सहित 10 याचिकाकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग विश्लेषक (खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला) सेवा नियमावली, 2017 के नियम 8(2) में वर्ष 2020 में किए गए संशोधन तथा भर्ती विज्ञापन में निर्धारित शैक्षिक योग्यता को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि खाद्य प्रौद्योगिकी, डेयरी प्रौद्योगिकी, ऑयल टेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी जैसी विषयगत डिग्रियों को भी भर्ती के लिए पात्रता में शामिल किया जाना चाहिए।अदालत ने स्पष्ट किया, दोनों पदों की प्रकृति अलग खंडपीठ ने अपने फैसले में कनिष्ठ विश्लेषक (खाद्य) और खाद्य विश्लेषक के पदों के बीच कानूनी अंतर को महत्वपूर्ण माना। अदालत ने कहा कि दोनों पद अलग हैं और उनके लिए निर्धारित सेवा नियम भी अलग-अलग कानूनी प्रावधानों के तहत संचालित होते हैं।

डीजीपी ने शहीद पुलिसकर्मियों के परिजनों को सौंपे 38 करोड़ के चेक

लखनऊ (आससे)। पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश राजीव कृष्ण ने गुरुवार को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ हुए एमओयू के तहत पुलिस सैलरी पैकेज योजना के अंतर्गत आकस्मिक दुर्घटना में मृत और दिव्यांग पुलिसकर्मियों के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक वितरित किए।डीजीपी ने 21 मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों और 2 दिव्यांग पुलिसकर्मियों सहित कुल 23 लाभार्थियों को 38 करोड़ 05 लाख रुपये की धनराशि के चेक प्रदान किए। इस अवसर पर डीजीपी ने मृत पुलिसकर्मियों के परिजनों से व्यक्तिगत रूप से भेंट कर उनकी समस्याओं और जरूरतों की जानकारी ली। दिव्यांग पुलिसकर्मियों से भी मुलाकात कर उनका कुशलक्षेम जाना और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश पुलिस अपने कर्मियों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए सदैव प्रतिबद्ध है और कठिन परिस्थितियों में पूरी संवेदनशीलता के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी।कार्यक्रम में आईजी जीएसओ के.एस. इमैन्युअल, डीआईजी मुख्यालय मो. इमरान, बैंक ऑफ बड़ौदा के महाप्रबंधक शैलेंद्र कुमार सिंह और शाखा प्रबंधक शशिकांत सिंह उपस्थित रहे।

भाजपा मतदाता सूची को लेकर कांग्रेसके हर आरोपोंका देगी जवाब

नयी दिल्ली (आससे)। भारतीय जनता पार्टी अगले हफ्ते से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू करने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद कांग्रेस के उन दावों का जवाब देना है, जिन्हें भाजपा 'गुमराह करने वाल' दावे बताती है। ये दावे मतदाता सूची के 'विशेष गहन पुनरीक्षण' (एसआईआर) और भारत निर्वाचन आयोग से जुड़े हैं। इस प्रस्तावित अभियान के तहत, भाजपा जनता के सामने तथ्य रखेगी ताकि एसआईआरऔर निर्वाचन आयोग के कामकाज को लेकर विपक्ष की ओर से उठाये गये सवालों और आरोपों का जवाब दिया जा सके। पार्टी के सांसदों, विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है कि वे अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में लोगों तक इस अभियान को पहुंचाएं। भाजपा के सूत्रों के अनुसार, पार्टी 24 पन्नों का एक विस्तृत दस्तावेज तैयार कर रही है, जिसमें विपक्ष की ओर से उठाये गये सवालों और लगाये गये आरोपों के जवाब शामिल हैं। उम्मीद है कि यह दस्तावेज पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए जनसंपर्क गतिविधियों के दौरान एक संदर्भ सामग्री (रेफरेंस मटेरियल) के रूप में काम आयेगा। इस अभियान को सोशल मीडिया और अन्य संचार माध्यमों के जरिए भी चलाया जायेगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा जा सके और इस मुद्दे पर पार्टी का पक्ष रखा जा सके। विपक्ष के मौजूदा आरोपों का जवाब देने के साथ-साथ, बीजेपी उन घटनाओं को भी उजागर करने की योजना बना रही है, जिनमें उसका आरोप है कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए चुनाव आयोग और अन्य संस्थानों का दुरुपयोग किया था। पार्टी इन उदाहरणों का इस्तेमाल कांग्रेस की आलोचना का जवाब देने और जनता के सामने अपना पक्ष रखने के लिए करना चाहती है।

छात्रों की आड़ में सत्ता बदलने की साजिश-प्रधान

नयी दिल्ली (आससे)। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि छात्रों के हितों और व्यवस्था में सुधार के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली मकसद देश में अराजकता फैलाना और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करना है। खुले तौर पर सत्ता परिवर्तन और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना विरोध प्रदर्शन के पीछे की मंशा को स्पष्ट करता है। धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि देशहित, व्यवस्था को ठीक करने के दावे और छात्रों के हितों के नाम पर शुरू हुए विरोध प्रदर्शन का असली चरित्र अब किसी से छिपा नहीं है। खुले तौर पर सत्ता बदलने और बांग्लादेश से प्रेरणा लेने की बात करना स्पष्ट करता है कि यह छात्रों की आड़ में केवल देश में अराजकता फैलाने और राजनीतिक व्यवस्था को अस्थिर करने की सोची-समझी साजिश है। प्रधान ने कहा कि विदेशी ताकतों के दम पर सत्ता हासिल करने का सपना देखने वालों को समझना चाहिए कि भारत में सत्ता परिवर्तन केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है।

उन्होंने दावा किया कि देश की जनता अलोकतांत्रिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर चुनावी जनादेश का अपमान करने और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम नहीं मिलने पर कांग्रेस जनता के बीच संस्थाओं को लेकर अविश्वास पैदा करने की कोशिश करती है। उन्होंने एक्स पर लिखा, हार का शतक लगा चुके नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बार-बार जनता के जनादेश को अपमानित करते हैं। चुनावी प्रक्रिया से मनचाहा परिणाम न मिलने पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति अविश्वास पैदा करने की कांग्रेस की कोशिश और राजनीतिक स्वार्थ के लिए आये दिन जनता को परेशान करना इनका हमेशा से उद्देश्य रहा है। यह उसी लोकतंत्र विरोधी कांग्रेसी मानसिकता को दिखाता है जिसमें देशवासियों के अधिकारों को कुचल दिया गया था। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने राहुल गांधी पर संविधान और सांविधानिक संस्थाओं का अपमान करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जनता राहुल गांधी को बार-बार नकार चुकी है, लेकिन सत्ता की लालसा में वह जनादेश पर सवाल उठा रहे हैं। प्रधान ने लिखा, हाथ में संविधान लेकर घूमने वाले संविधान विरोधी राहुल गांधी को जनता बार-बार नकार चुकी है।

उज्जैनमें महामंडलेश्वर ज्योतिगिरिके अवैध आश्रम पर चला बुलडोजर

उज्जैन (एजेंसी)। धार्मिक नगरी उज्जैन में सिंहस्थ आरक्षित भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने एक बार फिर कड़ा रुख अपनाया है। शुक्रवार तड़के नगर निगम की टीम ने बड़ी कारवाई करते हुए कर्कराज पार्किंग और नृसिंहघाट क्षेत्र के समीप स्थित जूना अखाड़े के हरियाणा सेवा आश्रम पर बुलडोजर चला दिया। महामंडलेश्वर ज्योतिगिरिजी महाराज द्वारा सिंहस्थ की सुरक्षित जमीन पर होटलनुमा अवैध जी+3 (चार मंजिला) भवन तान लिया गया था, जिसे प्रशासनिक अमले (शेष पृष्ठ ११ पर)

बेगूसराय : ज्वेलरी दुकान से दिन दहाड़े ४० लाखके आभूषण की लूट

डेहरी ऑन सोन (आससे.)। बिहार के बेगूसराय में फुलवरिया बाजार में शुक्रवार को दिनदहाड़े बदमाशों ने करीब 40 लाख रुपए के सोने- चांदी के गहने और एक लाख रुपए नगद लूट लिए। दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए नकाबपोश बदमाशों ने मां पार्वती ज्वेलर्स दुकान में घुसते ही दहशत फैलाने के लिए करीब 15 राउंड हवाई फायरिंग की। अचानक (शेष पृष्ठ ११ पर)

रेलवे ट्रैक पर गड़बड़ी रोकनेके लिए ड्रोनसे निगरानी

नयी दिल्ली (आससे)। भारतीय रेलवे ट्रैक पर पथराव, चोरी और अवैध आवाजाही जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ड्रोन से निगरानी बढ़ा रहा है। कैमरों से लैस ड्रोन के जरिये संवेदनशील स्थानों पर नजर रखी जा रही है। इससे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान करने और स्टेशनों पर भीड़ को नियंत्रित करने में भी मदद मिल रही है। रेलवे सूत्रों के मुताबिक, मार्च 2027 तक ड्रोन की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 करने की योजना है। ईस्ट कोस्ट रेलवे ने अपने तीन मंडलों में 11 ड्रोन तैनात किए हैं। ये 284 स्टेशनों, 2,708 रूट किलोमीटर और 6,072 ट्रैक किलोमीटर के दायरे में निगरानी कर रहे हैं। इनमें खुर्दा रोड मंडल में चार, संबलपुर में छह और रायगढ़ा (शेष पृष्ठ ११ पर)



